और विभिन्न प्रशिक्षण तथा अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों तथा संबंधित कार्यकलापों का आयोजन करना शुरू कर दिया है ।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का लगभग 100 ब्लाक प्रति वर्ष की दर से विस्तार करने का प्रस्ताव है । राज्य जिला और निम्न स्तरों पर एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के आयोजन एवं कार्यान्वयन के लिए संस्थागत क्षमताओं के विकास के विद्यमान केंद्रीय प्रायोजित घटकों के अतिरिक्त, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के लोगों को खाना पकाने और रोशनी की न्यूनतम घरेलू ऊर्जा आवश्यकतायें प्रदान करने के लिए एक नया घटक एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना में जोडने का प्रस्ताव है । 1991-92 तक मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम 21 ब्लाकों में शुरू किया गया है । मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में चुनिंदाय ब्लाकों में कम से कम एक ब्लाक स्तरीय एकीकृत ऊर्जा ग्रामीण परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

3583. [*Transferred to 20th August, 1992*].

मध्य प्रदेश में कम विकास दर होना

3584. **श्री अजीत जोगी :**
श्रीमती कैलाशपति :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की विकास दर अन्य राज्यों की विकास-दर तुलना में कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी राज्यों की वार्षिक समेकित विकास दर और राज्यवार वार्षिक विकास दर कितनी-कितनी थी ; और

(घ) मध्य प्रदेश की विकास दर को बढाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के स्थिर मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद और अखिल भारतीय निवल घरेलू उत्पाद की राज्यवार वार्षिक विकास दरों को दर्शाने वाला एक विवरण (**नीचे देखिए**) संलग्न है । अनेक कारणों से राज्यों के बीच विकास दरें भिन्न-भिन्न होती हैं, उनमें से कुछ विभिन्न क्षेत्रों में आधारिक संरचना उद्योग तथा उद्यमशीलता के ऐतिहासिक रूप से असमान विकास के कारण तथा वर्षों में वर्ष प्रतिवर्ष परिवर्तन एवं अनुवर्ती सूखा तथा बाढ के कारण होती है ।

(घ) विकास दर में वृद्धि करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं । इन योजनाओं में कृषि, उद्योग आधारिक संरचना, सिंचाई ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के विकास के लिए निवेश शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, गरीबों के लिए सीधा रोजगार एवं आय उत्पन्न करने के लिए कुछ कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित किया जा रहा है । आठवीं पंचवर्षीय योजना (19-92-97) के दौरान कुछ विकास कार्यक्रमों को पुनः लागू किया जाएगा । आठवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत परिव्यय 11,100 करोड़ रुपए है ।

विवरण

सतत मूल्यों पर पिछले वर्ष से निवल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशतता परिवर्तन

क्र० सं०	राज्य	1987–88	1988–89	1989–90 [पी]	औसत
1	आंध्र प्रदेश	9.19	17.25	2.91	9.78
2	अरूणाचल प्रदेश	5.52	6.71	0.56	4.26
3	असम	5.50	2.02	11.31	6.28
4	बिहार	– 6.03	11.60	– 0.53	1.68
5	गोवा	6.45	21.60	2.62	10.22
6	गुजरात	–11.88	43.16	1.70	10.99
7	हरियाणा	–2.07	24.34	0.72	7.66
8	हिमाचल प्रदेश	0.21	8.50	10.81	6.51
9	जम्मू व कश्मीर*	–12.62	17.02	––	2.20
10	कर्नाटक	7.40	7.94	5.85	7.06
11	केरल	3.94	8.95	5.23	6.04
12	मध्य प्रदेश*	15.90	9.34	0.99	8.74
13	महाराष्ट्र	6.51	10.22	13.75	10.16
14	मणिपुर	5.98	5.25	0.20	3.81
15	मेघालय	9.05	4.21	8.00	7.09
16	नागालैंड	10.77	9.72	9.76	10.08
17	उड़ीसा	– 1.44	14.95	7.63	7.01
18	पंजाब	5.05	5.15	7.70	5.97
19	राजस्थान	– 6.93	38.57	– 3.10	9.51
20	सिक्किम	20.63	––	––	20.63
21	तमिलनाडु	6.27	4.15	7.18	5.87
22	त्रिपुरा	8.35	6.41	7.30	7.35
23	उत्तर प्रदेश	3.78	10.47	2.86	5.70
24	प० बंगाल	3.08	4.39	4.82	4.10
25	अखिल भारत स०घ०उ०	4.35	10.96	6.08	7.13

पी : अनंतिम

* : पुरानी श्रृंखलाओं (1970–71) पर आधारित।

– : संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं किये गये।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश को छोड़कर जिसके अनुमान सतत (1970–71) मूल्यों पर है, सभी राज्यों के सतत (1980–81) मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों से विकास दरें तैयार की जाती हैं। मध्य प्रदेश के अनुमान दूसरे राज्यों से वास्तव में तुल्यनीय नहीं हैं। मिजोरम सतत मूल्यों पर एन. एस. डी. पी. के अनुमान तैयार नहीं करता और अतः उपरोक्त तुलना में शामिल नहीं है।

स्रोत : क. संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक तथा संख्यिकी निदेशालय।
ख. राज्य घरेलू उत्पाद और सकल निर्धारित संगठन के अनुमान (विवरण–2)